भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5717

दिनांक 06.04.2022 को उत्तर देने के लिए

उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिले

5717. श्री श्याम सिंह यादव:

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिलों में किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है और उक्त कार्यों को करने वाली संस्थाओं/एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बेरोजगारी की उच्च दर को देखते हुए उक्त कार्यक्रम के तहत और जिलों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं

राज्यमंत्री (कारपोरेट कार्य मंत्रालय)

(राव इंद्रजीत सिंह**)**

(क) आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। ये जिले हैं चित्रकूट, बलरामपुर, श्रावस्ती, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, चंदौली, सोनभद्र और बहराइच।

इस कार्यक्रम का लक्ष्य उन पिछड़े जिलों के उन क्षेत्रों में तेजी से परिवर्तन करना है जो नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक उत्पादकता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये क्षेत्र इस प्रकार हैं, स्वास्थ्य एवं पोषण, स्कूली शिक्षा और आधारभूत अवसंरचना और कृषि एवं जल संसाधन तथा वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास। 49 मुख्य निष्पादन संकेतकों का चयन इन क्षेत्रों से किया गया है और जिलों के निष्पादन की निगरानी इन संकेतकों पर की गई मासिक प्रगति के आधार पर की जाती है जोकि चैंपियंस ऑफ चेंज पोर्टल (http://championsofchange.gov.in/site/coc-home/) पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम की व्यापक कार्यनीति किसी अतिरिक्त योजना को चलाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि प्रमुख निष्पादन संकेतकों में सुधार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की मौजूदा योजनाओं के तहत विकास कार्यों को कुशलता से कार्यान्वित किया जाए। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की व्यापक कार्यनीति, अभिसरण (केंद्र और राज्य की योजनाओं के बीच), सहयोग (केंद्र, राज्य, जिला प्रशासन, विकास भागीदारों एवं नागरिकों के बीच) और प्रतिस्पर्धा (जिलों के बीच) पर आधारित है। प्रत्येक माह, प्रमुख निष्पादन संकेतकों पर की गई प्रगति के आधार पर जिलों को रैंक दिया जाता है, और वे निष्पादन अनुदान/अतिरिक्त आवंटन के पात्र बन जाते हैं, और इससे उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है जिसके परिणामस्वरूप तेजी से सुधार होता है। कार्यक्रम की अन्य कार्यनीति भारत सरकार के संयुक्त सचिव/अपर सचिव स्तर के अधिकारियों को प्रत्येक जिले के लिए केंद्रीय प्रभारी अधिकारी के रूप में नामित करना है। इन प्रभारी अधिकारियों की भूमिका उनके लंबे अनुभव के आधार पर जिला प्रशासन का मार्गदर्शन करना है।

कम समय में, कड़ी निगरानी और प्रतिस्पर्धा के कारण, उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिलों ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

(ख) और (ग) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न क्षेत्रों के संकेतकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो इन अपेक्षाकृत अल्प विकसित जिलों में जीवन की गुणवत्ता या नागरिकों की आर्थिक उत्पादकता में सुधार करते हैं। सामान्य विकास सुनिश्चित करके, कार्यक्रम इन पिछड़े जिलों में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में मदद करता है। यद्यपि वर्तमान में, कार्यक्रम के तहत अधिक जिलों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, परन्तु मौजूदा जिलों की प्रगति को और तेज करने पर ध्यान जारी है।

*****